मुद्रास्फीति नियंत्रण पर फोकस

[स्रोत: द हिंदू](#)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) ने मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिये फरवरी 2024 में भी रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है।

- MPC का उद्देश्य **+/- 2% के बैंड के भीतर 4% मुद्रास्फीति का मध्यम अवधि का लक्ष्य हासिल करना** है।
- MPC ने **निभाव (Accommodation) को वापस लेने** पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो।
    - उदार रुख का मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये **मुद्रा आपूर्ति का विस्तार** करने के लिये तैयार है।
    - निभाव को वापस लेने का मतलब **प्रणाली में धन की आपूर्ति को कम करना** होगा जो मुद्रास्फीति पर और लगाम लगाएगा।
- RBI के एक हालिया वक्तव्य में कहा गया है कि दिसंबर 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 5.7% हो गई, जो मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति से प्रेरित है और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता पर बल देती है।
- MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने के लिये **आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित** करती है। RBI **मौद्रिक नीति की विभिन्न लिखतों** को नियोजित करके **मुद्रास्फीति और अपस्फीति** को नियंत्रित करता है जैसे:
    - रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, खुला बाज़ार परिचालन, सांविधिक तरलता अनुपात (SLR), नकद आरक्षित अनुपात (CRR), चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) और बाज़ार स्थिरीकरण योजना।

मौद्रिक नीति की मात्रात्मक लिखतें

QUANTITATIVE INSTRUMENTS OF MONETARY POLICY

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)

- **रेपो दर (RR):** वह दर जिस पर **भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है।** यहाँ, RBI **प्रतिभूतियों की खरीद** करता है।
- **रिवर्स रेपो दर:** वह **दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है।** रेपो दर के के विपरीत।
- यदि RBI **सख्त मौद्रिक नीति** का संकेत देना चाहता है, तो वह **रेपो दर में वृद्धि** करेगा; बैंक अपनी **उधारी दरों में वृद्धि** करेंगे।

बैंक दर

- यह एक **दीर्घकालिक दर** है (रेपो दर अल्पकालिक है) जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को धन उधार देता है।
- **बैंक दर में वृद्धि से ऋण/जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि** होगी और इसी तरह इसमें कमी से ऋण/जमा पर ब्याज दरों में कटौती होगी।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR)

- SLR **जमाओं की न्यूनतम हिस्सेदारी** है जो वाणिज्यिक बैंकों को अभारित **सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी एवं स्वर्ण जैसी सुरक्षित व चल आस्तियों में रखना होता है।**
- यदि RBI **मौद्रिक नीति को सख्त करना चाहता है, तो वह SLR में वृद्धि** करेगा।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

- बैंकों को अपनी **जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास नकदी के रूप में रखना आवश्यक** है।
- **CRR में वृद्धि के साथ ही बैंक ऋण की दरों में वृद्धि** कर देते हैं।

खुला बाजार परिचालन (OMOs)

- इनमें बैंकिंग प्रणाली में **टिकाऊ चलनिधि को इंजेक्ट/अवशोषित करने के लिये** रिज़र्व बैंक द्वारा **सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री** शामिल है।

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

और पढ़ें: [RBI ने नीतिगत दरें अपरिवर्तित](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/focus-on-inflation-control